The Government has been promoting aquaculture due to dwindling shrimp production from the traditional fishing grounds as a result of over-exploitation of the natural resources. In this context, taking also into consideration the potential for aquaculture development in India, the government had identified aquaculture as an extreme focus area. MPEDA have, however, not laid an over emphasis on augmentation of exports sourced from aquaculture at the cost of its other activities relating to other sectors.

**Conservation works in colliery area of Bihar**

3400. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the name of the works undertaken in respect of conservation efforts and development of roads, etc. in colliery areas of Bihar in the years 1995-96; and

(b) the physical targets and achievements, year-wise in regard to each item?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) As per information furnished by Coal India Limited, the details of sand stowing for conservation of coal and development of roads undertaken by Bharat Coking Coal Limited, Eastern Coalfields Limited and Central Coalfields Limited in colliery areas of Bihar in the year 1995-96 are given below:—

| Name of work | 1995-96 | |
|---|---|---|
| | Target | Achievment |
| Sand stowing for conservation (Lakhs cubic metres) | 34.50 | 22.96 |
| Development of roads (Kilometres) | 89.73 | 54.99 |

**भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा दी गई रॉयल्टी**

3401. **श्री सोमपाल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1991 में उदारीकरण की नीति को लागू किए जाने के बाद से भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों और अन्य कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली रॉयल्टी की राशि में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान विदेशों को कितनी रॉयल्टी का भुगतान किया गया और इससे पहले के वर्षों की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई;

(ग) रॉयल्टी के भुगतान की राशि में इस वृद्धि के लिए कौन-कौन से कारक उत्तर दायी हैं और क्या सरकार इस स्थिति को संतोषजनक मानती है; और

(घ) इससे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हुई है या होने की संभावना है?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**बैलाडीला से जापान को लौह अयस्क का निर्यात**

3402. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला लौह अयस्क खानों से जापान को लौह अयस्क के निर्यात का वर्तमान अनुबंध 1996 में समाप्त होने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इन खानों से उत्खनन का कार्य जारी रखने का विचार रखती है?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया):** (क) और (ख) बैलाडीला लौह अयस्क के निर्यात के लिए जापान स्टील मिल्स के साथ हुआ दीर्घावधि करार मार्च '96 में समाप्त हो चुका है। तथापि बैलाडीला क्षेत्र से लौह अयस्क की सीमित मात्रा सहित लौह अयस्क के निर्यात हेतु, जो कि घरेलू आवश्यकताओं के लिए अधिशेष है, दूसरा दीर्घावधि करार 1.4.1996 से 31.3.2001 तक, 5 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किया गया है।